



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)
Part II--Section 3--Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 466] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 1995/श्रावण 11, 1917 (शक)
No. 466] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 1995/SRAVANA 11, 1917

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना संख्या 8/(आर ई-95)/92-97

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1995

क्र.आ. 702(अ).--विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 के 22) के खण्ड-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निर्यात एवं आयात नीति 1992-97 (संशोधित संस्करण मार्च 1995) में इस प्रकार संशोधन करती है :--

2. पैरा 46 के उत्तरार्ध के प्रथम दो वाक्यों को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाए :--

“15% रियायती सीमाशुल्क या शून्य सीमाशुल्क ई पी सी जी स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति पूंजीगत माल आयात करने की बजाए उसे घरेलू उत्पादक से ले सकता है। पार्टियों के बीच माल खरीदने के ऐसा दृढ़ करार होने पर, घरेलू उत्पादक इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त पूंजीगत माल के उत्पादन के लिए अपेक्षित घटक आयात करने के लिए 15%सीमाशुल्क की रियायती दर पर या शून्य सीमाशुल्क पर, जैसी भी स्थिति हो, के लिए आवेदन कर सकता है।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 8/(RE-95)/92-97

New Delhi, the 2nd August, 1995

S.O. 702 (E).--In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendment in the Export and Import Policy, 1992-97, Revised Edition : March, 1995), namely :--

2. The first two sentences of the second half of paragraph 46, shall be amended to read as under :--

"A person holding a licence, either under fifteen per cent concessional duty or zero duty EPCG Scheme, may source the capital goods from a domestic manufacturer instead of importing them. In the event of a firm contract between the parties for such sourcing, the domestic manufacturer may apply under the scheme for the import of components required for the manufacturer of the said capital goods, at a concessional rate of customs duty of 15% or zero duty, as the case may be."

3. This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade